शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार से
मध्यप्रदेश

प्रत्येक छात्र को दो हजार रुपए दें राज्य सरकारें

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के लिए 2,000 रुपए प्रति माह प्रदान करें, जो एक बाल संरक्षण गृहों (सीसीआई) में था और अब कोरोना वायरस महामारी के दौरान उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया है।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को 30 दिनों के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाइयों की सिफारिश के आधार पर वहां रहने वाले बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं के लिए किताबें और स्टेशनरी सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना चाहिए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीसीआई में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यक संख्या उपलब्ध कराई जाए। इस पीठ में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी भी शामिल थे।

1,45,788 बच्चों को परिवारों या अभिभावकों को सौंपा: पीठ ने ये भी कहा कि कोविड-19 महामारी जब शुरू हुई थी तब 2,27,518 बच्चे सीसीआई में थे और अब 1,45,788 बच्चों को उनके परिवारों या अभिभावकों को सौंप दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्यों को उनकी शिक्षा के लिए प्रति माह 2,000 रुपए का भुगतान करना होगा और यह राशि बच्चों के परिवारों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई की सिफारिश पर दी जानी चाहिए।

अच्छी खबर: 364 कर्मचारियों को सौगात

30 साल की सेवा वालों को मिला तृतीय समयमान वेतनमान

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

नगर निगम में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को निगम प्रशासन ने बड़ी सौगात दी है। प्रशासन ने विभिन्न श्रेणी में 30 वर्षों से कार्यरत 364 कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासक कवीन्द्र कियावत और निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। निगम के विभिन्न पदों पर कार्यरत तृतीय श्रेणी के 55 कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी के 309 कर्मचारियों को उनकी 30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की दिनांक से तृतीय समयमान वेतनमान दिया गया है।

निगम की विभागीय समयमान वेतनमान समिति की अनुशंसा पर प्रशासक के संकल्प क्रमांक 490 दिनांक 14 दिसंबर 2020 अनुसार निगम के 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले पात्रताधारी अधिकारियों, कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश मंगलवार को निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने जारी किए।

जारी आदेश के अनुसार निगम ने सहायक लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 15600-39100-5400 का समयमान वेतनमान, तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों पर कार्यरत 55 कर्मचारियों को 9300-34800-3200 का समयमान वेतनमान दिया गया है, जबकि चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर कार्यरत 309 कर्मचारियों को 5200-20200-2100 का समयमान वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

Published in 16 Dec 2020 print edition of Raj Express

13 दिन में दूसरी बार 50 रुपए हुई महंगी रसोई गैस, अब 700 रु. में मिलेगा घरेलू गैस सिलेण्डर

कामर्शियल गैस सिलेण्डर में 36 रुपए की बढ़ोत्तरी, अब 1337.50 रुपए में मिलेगा, उपभोक्ताओं के खाते में गैस सब्सिडी आएगी या नहीं, एजेंसी वालों को भी नहीं पता

भोपाल । दिसंबर माह में दूसरी बार बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेण्डर (रसोई गैस) की कीमतों में मंगलवार को 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। यह वृद्धि केंद्र सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों ने की है। इस बढ़ोतरी के बाद भोपाल में 14.2 किलोग्राम वाला नान सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर, अब घरेलू उपभोक्ताओं को 700 रुपए में मिलेगा। इस बढ़ोत्तरी से गैस उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ना तय है। हालांकि 2 दिसंबर को पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेण्डरों के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। बीते 15 दिनों में घरेलू गैस सिलेण्डर के दाम में 100 रुपए की वृद्धि हो गई है। इधर, 19 किलोग्राव वाले कामर्शियल (व्यावसायिक) गैस सिलेण्डर के दाम में दूसरी बार 36 रुपए की वृद्धि हुई है। अब भोपाल में व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के दाम 1301.50 रुपए से बढ़कर 1337.50 रुपए हो गया है। इससे पहले 2 दिसंबर को कामर्शियल सिलेण्डर के दाम में 54.50 रुपए की वृद्धि की गई थी। बीते 15 दिनों में कामर्शियल सिलेण्डर 90.50 रुपए महंगा हुआ है।

15 दिन में इतनी बढ़ी कीमतें

पिछले 15 दिनों से अब तक 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेण्डर 100 रुपए महंगा हुआ। इसी प्रकार 19 किलोग्राम वाला व्यावसायिक गैस सिलेण्डर 90.50 रुपए मंहगा हुआ है।

भोपाल में ऐसी बढ़ी कीमतें

भोपाल में पिछले 15 दिनों में 14.2 किलोग्राम वाला गैस सिलेण्डर (नॉन सब्सिडाईज्ड) 3 दिसंबर को 650 रुपए रेट बढ़ाया गया। इसी तरह 15 दिसंबर से गैस सिलेण्डर के रेट बढ़कर 700 रुपए हो गया। ऐसे में दूसरी बार 50 रुपए की गैस सिलेण्डर की कीमतों में वृद्धि हुई है।

19 किलो वाले सिलेण्डर के ऐसे बढ़े रेट

2 दिसंबर को व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रेट 1247 रुपए था। सरकार द्वारा 3 दिसंबर को व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का रेट 54.50 रुपए बढ़ाकर 1301.50 रुपए कर दिया गया। इसी तरह 15 दिसंबर तक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का रेट 36 रुपए बढ़ाकर 1337.50 रुपए कर दिया गया है।

छात्र विरोधी रुख पर सीबीएसई को फटकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को उसके 'विद्यार्थी विरोधी रुख' के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि वह कई मामलों में विद्यार्थियों को उच्चतम न्यायालय तक ले जाकर उनके साथ 'शत्रु' जैसा व्यवहार कर रहा है॥। मुख्य न्यायाधीश ड़ीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने यह टिप्पणी बोर्ड़ द्वारा एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए की। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि कोविड़-19 की वजह से रद्द परीक्षा से प्रभावित विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई द्वारा लाई गई पुनः मूल्यांकन योजना अंक सुधार के आवेदकों पर भी लागू होगी। अदालत ने कहा हम सीबीएसई का विद्यार्थी विरोधी रुख पसंद नहीं करते।

दसवीं बारहवीं की परीक्षाओं को लेकर भोपाल संभाग में अधिकारियों की चिंता सामने आई

संभाग के प्रत्येक जिले में ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू

भोपाल(आरएनएन)। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर भोपाल संभाग में अधिकारी चिंतित हुए हैं। संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय ने अध्यापन में गति लाने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग का सिस्टम तैयार किया है। कुछ माह पूर्व राजगढ़ में शुरू किए गए इस प्रयोग की सफलता को लेकर संभाग के समस्त जिलों में इस प्रकार की मॉनिटरिंग का कदम उठाया गया है।

इस संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख दिया गया है कि वह मंगलवार से नियमित रूप से ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे।पत्र में संयुक्त संचालक राजीव तोमर द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि कोविड-19 के समय में कक्षाएं डिजिटल मोड से

अनियमितताओं पर जिला शिक्षा अधिकारी होंगे जवाबदार

संचालित इसके साथ ही प्राचार्य ऑनलाइन मोड़ से समीक्षा कर रहे हैं, अब जरूरत है कि वर्तमान परिपेक्ष में लोक शिक्षण द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में हाई सेकंडरी हाई स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था जिला स्तर से सुनिश्चित होगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु पायलट आधार पर जिला राजगढ़ में प्रयोग किया गया है, जिसमें शत प्रतिशत सफलता मिली है। इस कारण समस्त जिलों में यही व्यवस्था अनिवार्य की गई है। ज्वाइंट डायरेक्टर राजीव ने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रतिदिन न्यूनतम 5 हाई स्कूल हाई सेकंडरी विद्यालयों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करनी होगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग गूगल मीट व्हाट्सएप वीडियो अथवा अन्य उपयुक्त की जाएगी।

विद्यालयों के प्राचार्य को लिंक भेजा जाए अथवा उनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया जाए

जेडी राजीव तोमर ने साफ कहा है कि विद्यालयों का चयन किया जाएगा। उक्त विद्यालयों के प्राचार्य को लिंक भेजा जाए अथवा उनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया जाए। सभी प्राचार्य संबंधित प्रारूप से लिंक से जुड़ेंगे। व्हाट्सएप वीडियो कॉल का रिप्लाई देना होगा। वीडियो कॉल कर रिप्लाई ना देने पर प्राचार्य एवं उप प्राचार्य की अनुपस्थिति मानी जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन ऑनलाइन किए जाने वाले विद्यालयों में शिक्षक की उपस्थिति साफ-सफाई रंगाई पुताई कक्षाओं का संचालन पुस्तकालयों का अवलोकन एवं विभागीय गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली जाएगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग में पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसमें विद्यालय का नाम मॉनिटरिंग का दिनांक मॉनिटरिंग के बिंदु निर्धारित होंगे। यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित है तो उसका विवरण एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में भी विवरण दर्ज किया जाएगा। अधिकारी ने कहा है कि मंगलवार से सभी स्कूलों में ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रतिमाह ऑनलाइन मॉनिटरिंग का कार्य क्षेत्र में किए गए भ्रमण के अतिरिक्त होगा। क्षेत्र कि मैदानी भ्रमण की मॉनिटरिंग का कारी पूर्व की तरह जारी रखा जाएगा। माह के अंतिम प्रतिवेदन भी लिया जाएगा। उक्त मॉनिटरिंग विद्यालयों की समीक्षा में यदि कोई अनियमितता पाई गई तो उसका उत्तरदाई भी जिला शिक्षा अधिकारी होगा।

व्याख्याताओं की वेतन विसंगति दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग में प्रक्रिया शुरू

एक दिन पहले व्याख्याता मिले थे पीएस से, मंगलवार को दिन भर हुई भागदौड़

भोपाल (आरएनएन)। प्रदेश में उपदराज होकर लगातार विरोध से रहे व्याख्याताओं की समस्या का एकमात्र शिक्षा विभाग को हुआ है। एक दिन पहले ही लेक्चरारों और प्राचार्य का एक दल विभाग की प्रमुख सचिव से मिला था, जहां वेतन विसंगति से होने वाले अनेक नुकसान गिनाए गए थे। अगले ही दिन मंगलवार से इस विषय में काम शुरू हो गया है। मंगलवार को संचालनालय और लोक शिक्षण संचालनालय के बीच लगातार जानकारी जुटाने का काम चला। दूरभाष पर संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों से भी संपर्क हुए।

बताना होगा कि व्याख्याताओं ने अपनी वेतन विसंगतियों को लेकर सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव दीपा अरुण शर्मा से मुलाकात की थी। व्याख्याता एवं प्राचार्य संवर्ग की समस्याओं के निराकरण हेतु संयुक्त प्रदेश शिक्षक संघ, प्रांतीय सरकारी सलेव व्याख्याता एवं प्राचार्य संघ, समग्र शिक्षक व्याख्याता एवं प्राचार्य कल्याण संघ, एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रमुख पदाधिकारियों जगदीश सिंह राठौर, महामंत्री शिक्षक संघ, के के गौर संभागीय अध्यक्ष शिक्षक संघ, प्रदेश अध्यक्ष अरुण चिकारवार, मुकेश शर्मा एवं प्रांतीय संयोजक पीएस परिहार सहित प्रमुख प्रांतीय पदाधिकारी भरत व्यास, सुधाकर पाराशर, डॉ अनिल कुशवाहा, रोहित सिंह, रविकरण जैन, महेश सोलंकी, महान सोनगरे भावना शर्मा एवं सोनगरे संगीता सक्सेना सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

शिक्षकों को पदोन्नति पदनाम के विषय में भी सोचना होगा

इधर शिक्षक और व्याख्याता शिक्षकों ने भी पदोन्नति पदनाम के लिए विभाग पर दबाव बनाया है। व्याख्याता शिक्षक संवर्ग संघों के संयोजक सुभाष शर्मा का कहना है कि विभाग को इस विषय में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री की घोषणा को हुए पूरे 5 साल पीछे हो चुके हैं लेकिन अब तक इसका पालन नहीं किया गया है। शर्मा का कहना है कि अपने घोषणा पूर्ण तक में अभी तक प्रदेश में हजारों शिक्षक बिना पदोन्नति पदनाम का लाभ लिए रिटायर हो गए हैं। विभाग का यह रवैया शिक्षकों के प्रति न्याय संगत नहीं कहा जाएगा।

प्रमुख सचिव शर्मी ने प्रमुख मुद्दों पर जताई थी सहमति

बैठक में व्याख्याता, प्राचार्य संवर्ग की समस्याओं एवं वेतन विसंगति से संबंधित सभी बिंदुओं पर प्रमुख सचिव दीपा अरुण शर्मा, उप सचिव अमृत मीणा, संयुक्त लोक शिक्षण अधिकारी किशोर संचालक लोक शिक्षण के डिप्टी, सभी संभाग अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। इस का नेतृत्व भरत व्यास द्वारा किया गया एवं विसंगति के बारे में प्रमुख सचिव एवं सभी अधिकारियों को विस्तार से बताया। प्रमुख सचिव द्वारा ध्यान में पूरी बात सुनी एवं निर्णय लिए कि व्याख्याताओं की विसंगति संबंधी फाइल को तैयार कर मेरे अवलोकन के लौटने पर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। हाईस्कूल प्राचार्य का पद समाप्त करने के संबंध में भी चर्चा की गई जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

इलेक्टोरल कॉलेज ने जो बाइडन की जीत पर लगाई मुहर

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के निर्वाचन मंडल (इलेक्टोरल कॉलेज) ने जो बाइडन को देश के राष्ट्रपति और भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के पद के लिए बहुमत देकर उनकी जीत की औपचारिक पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कानूनी लड़ाई को विराम लग गया है, जिसमें चुनाव में व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी होने का आरोप लगाया गया था।

बाइडन को देश के 50 प्रांतों ने 306 इलेक्टोरल कॉलेज मिलने की पुष्टि की है। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत होती है। कानून के अनुसार इलेक्टोरल कॉलेज की बैठक दिसंबर के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले पहले सोमवार को होती है। इस दिन सभी 50 प्रांतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के निर्वाचक अपना मत डालने के लिए बैठक करते हैं। हालांकि निर्वाचक मंडल की बैठक मात्र औपचारिकता होती है, लेकिन यह बैठक इस साल पहले की तुलना में अधिक चर्चा में रही, क्योंकि देश के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप ने हार स्वीकार करने से इन्कार करते हुए चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं।

अब आगे क्या होगा : अब मतदान के नतीजों को वाशिंगटन भेजा जाएगा। यहां छह जनवरी को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में आधिकारिक तौर पर उनकी गिनती होगी। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति माइक पेंस करेंगे। इसके बाद बाइडन का राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने का रास्ता खुल जाएगा।

जो बाइडन

नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे ट्रंप : व्हाइट हाउस से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाइडन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उधर, व्हाइट हाउस के एक सलाहकार उस सलाह का मजाक उड़ाया है, जिसमें छह जनवरी को होने वाली बैठक में इलेक्टोरल कॉलेज की वैकल्पिक सूची भेजने की सिफारिश की थी।

बाइडन को पुतिन ने दी बधाई: रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने मंगलवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन को जीत की बधाई दी। बता दें कि इससे पहले रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा था कि जब तक आधिकारिक तौर पर विजेता की पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक वह बाइडन को जीत की बधाई देने का इंतजार करेंगे।

नर्सिंग फर्जीवाड़े की सौंपी जाए जांच रिपोर्ट

ग्वालियर, न.सं.। जीवाजी विश्वविद्यालय की राज्यपाल कोटे के कार्यपरिषद सदस्य मंगलवार को प्रभारी कुलपति एवं कुलसचिव से मुलाकात कर छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया। कार्यपरिषद सदस्य अनूप अग्रवाल और डॉ. मुनेंद्र सिंह सोंलकी ने प्रभारी कुलपति प्रो. एसके शुक्ला को बताया कि बीएससी नर्सिंग फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन उन्हें क्यों नहीं दी जा रही है। साढ़े 16 करोड़ रुपए के टेंडर क्यों जारी किए जा रहे हैं। जिस पर प्रो. शुक्ला ने कहा कि कुलपति प्रो संगीता शुक्ला के आने के बाद ही जांच रिपोर्ट और टेंडर प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इससे पहले कार्यपरिषद सदस्य डॉ. संगीता चौहान सुबह कुलसचिव डॉ आंनद मिश्रा से मिलने पहुंची। जहां उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा दो वर्षों से पीएचडी प्रवेश कराने में विवि की ओर से असमर्थता क्यों जताई जा रही है। विवि यह तय करें कि परीक्षा कब कराई जाएगी।

अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने से पहले देना होगा सुनवाई का मौका

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को अब सुनवाई के बगैर सेवा से नहीं हटाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर दिया है। ऐसे किसी भी मामले में अब अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कलेक्टर और संभागायुक्त के कार्यालय में अपील की जा सकेगी। संबंधित अधिकारियों को 15-15 दिन में अपील का निराकरण करना होगा।

10 जुलाई 2007 को जारी नियमों के तहत कार्यकर्ताओं को अपील का अवसर नहीं दिया जाता था। कार्य में लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार के मामलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को परियोजना अधिकारी हटा देते थे। अब नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। ऐसे किसी भी मामले में अब कार्यकर्ता को नोटिस देकर अपनी सफाई देने के लिए तीन दिन का समय देना होगा। सुनवाई के बाद गुण-दोष के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के अनुमोदन से परियोजना अधिकारी सेवा समाप्ति का निर्णय लेकर आदेश जारी कर सकेंगे। आदेश मिलने के सात दिन में कार्यकर्ता कलेक्टर को पहली अपील कर सकेंगे।

एमपी बोर्ड में 55 फीसद अंक आए तो ए ग्रेड

भर्ती प्रक्रिया में संशोधन के अनुसार अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए एमपी बोर्ड में 55 फीसद अंक आने पर ए ग्रेड माना जाएगा। जबकि सहायिकाओं और मिनी कार्यकर्ता के लिए 60 फीसद अंक जरूरी होंगे।

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

राजा भोज मार्ग, कोलार रोड, भोपाल - 462016 (म.प्र.)

दूरस्थ शिक्षा का मध्यप्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय

प्रवेश सूचना 2020-21

एम.बी.ए., बी.बी.ए., बी. कॉम., एम.ए., एम.एस.डब्ल्यू., बी.ए., एम.एससी., बी.एससी., एम.एससी.(आई.टी.), बी.एससी.(आई.टी.) विभिन्न डिप्लोमा कोर्स एवं प्रमाण पत्र कोर्स **अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2020 तथा विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 10.01.2021.**

आवेदन करने की लिंक

https://mpbou.mponline.gov.in/portal/Index.aspx

क्षेत्रीय केन्द्र :- 1. भोपाल - 0755-2492273, **2. इन्दौर** - 0731-2465689, **3. ग्वालियर** - 0751-2345559, **4. जबलपुर** - 9893151661, 9893523754, **5. रीवा** - 07662-250410, 9425124312, **6. सतना** - 07672-404440, **7. सागर** - 07582-264130, **8. उज्जैन** - 0734-2526993, **9. छिंदवाड़ा** - 07162-243716, **10. होशंगाबाद** - 07574-254096, **11. बड़वानी** - 07290-222099, अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट - **www.mpbou.edu.in**

म.प्र. माध्यम/99233/2020

कुलसचिव

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी।

शिक्षक ने छात्र को केबल से पीटा

ग्वालियर, न.सं.

कोचिंग का एक शिक्षक उस समय बौखला गया जब उसको छात्र ने प्रश्न का जवाब नहीं दिया। बौखलाए शिक्षक ने लेपटॉप चार्जर के केबल से छात्र को जमकर धुन डाला। शिक्षक द्वारा मारपीट का शिकार छात्र अपने परिजनों को लेकर थाने पहुंचा और शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर शिकायती आवेदन दिया। नया संतर मुरार में रहने वाला अरूर शर्मा सांई एक्सीलेंस क्लासेस में कोचिंग पढ़ने के लिए जाता है। मंगलवार को अरूर से कोचिंग संचालक नितिन शर्मा ने जो काम दिया था उसके प्रश्न का उत्तर पूछा। जब छात्र ने प्रश्न को याद नहीं करने की बात शिक्षक से कही तो उनका पारा चढ़ गया और नितिन ने अपने लेपटॉप के चार्जर की केबल को निकालकर छात्र अरूर शर्मा की मारपीट कर घायल कर दिया। छात्र घर पहुंचा तो उसकी हालत परिजनों ने देखी और चोट लगने का कारण पूछा। जब शिक्षक की बेरहमी के बारे में छात्र ने बताया तो परिजन उसे लेकर मुरार थाने पहुंचे और पुलिस से छात्र को बेरहमी से पीटने के बारे में बताया। छात्र शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बात पुलिस से कह रहा था। लेकिन पुलिस ने शिकायती आवदेन लेकर छात्र के साथ मारपीट की जांच प्रारंभ कर दी है।

संत कॉलेज में उद्यमिता विकास पर वेबिनार का आयोजन

संत हिरदाराम नगर। संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय में ई-सेल उद्यमिता प्रकोष्ठ ने उद्यमिता विकास पर पर वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार की मुख्य वक्ता के डॉ. दीपक मोटवानी, डिप्टी जनरल मैनेजर, कॉर्पोरेट रिलेशन, आई सेक्ट ग्रुप थे। मोटवानी उद्यमिता के क्षेत्र में मौजूद अवसरों, चुनौतियों तथा उनके समाधान के मार्गों से छात्राओं को अवगत कराया। मोटवानी ने कहा कि आज के समय में उद्यमिता समय की मांग है । छात्राओं को अपना कौशल विकास इस प्रकार करना चाहिये कि वे रोजगार प्राप्त करने के बजा रोजगार का सृजनकर औरों को काम दे सकें। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. डालिमा पारवानी ने कहा कि यह वेबिनार अवश्य ही छात्राओं के लिए ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी सिद्ध होगा एवं महाविद्यालय की छात्राएं अवश्य ही उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रयास करेंगी। कार्यक्रम की वक्ता का परिचय एवं स्वागत भाषण मधु सिंह, सहायक प्राध्यापक कम्प्युटर साइंस, कार्यक्रम की रूपरेखा डॉ. मीना बरसे, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय द्वारा एवं आभार प्रदर्शन प्रतिभा मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय ने किया।

इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डीन बने डॉ.पटेल

इंदौर। सेवानिवृत्त मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर डॉ. जीएस पटेल को इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का डीन नियुक्त किया गया है। डॉ. रामगुलाम राजदान मेडिकल डायरेक्टर समेत तीन पदों पर रहेंगे। डॉ. पटेल को चिकित्सा क्षेत्र में 40 साल का अनुभव है। प्रसिद्ध पीडियाट्रिशियन के रूप में वे चिकित्सा शिक्षा विभाग के कमिश्नर व डायरेक्टर रह चुके हैं। कई सालों तक स्टेट मेडिकल काउंसिल और पैरामेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष व सागर, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डीन भी रहे हैं। वहीं डॉ. राजदान एमजीएम मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग के एचओडी रहे हैं। मानसिक चिकित्सालय के अधीक्षक पद का दायित्व भी संभाला है। ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला में डायरेक्टर होने के अलावा उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन की कई फैलोशिप का भी अनुभव है।

गोरखी स्कूल को विकसित कर बनेगा अटल संग्रहालय

ग्वालियर, न.सं.

शहर के विकास कार्यों को लेकर अब संभागीय आयुक्त भी मैदान में आ चुके हैं। मंगलवार की शाम को उन्होंने महाराज बाड़े पर स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए गए डिजिटल संग्रहालय को देखा तथा इसकी सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने संग्रहालय के पास गोरखी स्कूल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री सक्सेना ने गोरखी स्कूल को विकसित करने के साथ ही अटल जी की स्मृतियों को सहेजने के लिए अटल संग्रहालय को बनाने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। संभागीय आयुक्त ने डिजिटल संग्रहालय के निरीक्षण के दौरान इसकी खूबसूरती व अत्याधुनिक तकनीक से दर्शाई गई जानकारी की सराहना की। श्री सक्सेना ने कहा कि गोरखी स्कूल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शिक्षा ली है और ऐसे में जरूरी है कि इस स्कूल को विकसित करने के साथ साथ अटल जी की स्मृतियों को भी सहेजा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिसर के एक हिस्से में अटल जी के नाम पर संग्रहालय बनाने की रूपरेखा पर कार्य किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधीश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयति सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी

ग्वालियर। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6वीं के आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर से बढ़ाकर 29 दिसंबर कर दी है। वहीं कक्षा 9वीं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। यह जानकारी जवाहर नवोदय विद्यालय के उपायुक्त पी.एस. सरदार ने दी है।

अतिथि शिक्षक पदों के लिए आदेश जारी

ग्वालियर, न.सं.। मध्यप्रदेश लोक शिक्षण आयुक्त ने प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य को हायर सेकेण्डरी और हाईस्कूल में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति न होने तथा प्रत्येक विषय के एक शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक विषय के स्वीकृत पद के विरुद्ध अधिकतम एक अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने हेतु पद प्रदर्शित किए गए हैं। जिन विद्यालयों में कुल नामांकन (कक्षा 9-12) के विरुद्ध लगातार एक सप्ताह तक औसत उपस्थिति 80 प्रतिशत या इससे अधिक होने की स्थिति में विद्यालय की स्वीकृत पदसंरचना अनुसार रिक्त पद हेतु अतिथि शिक्षकों की मांग संलग्न प्रारूप में विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त होने तथा विमर्श पोर्टल पर प्रदर्शित अतिरिक्त रिक्ति के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षक रखा जाए अन्यथा संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की ऑनलाईन ज्वाइनिंग की व्यवस्था शीघ्र ही जीईएमएस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है।

विरोध स्वरूप पेंशनर्स दिवस नहीं मनाएंगे सेवानिवृत्त कर्मचारी

ग्वालियर। शासन की उपेक्षापूर्ण नीतियों का विरोध करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी इस बार 17 दिसम्बर को पेंशनर्स दिवस नहीं मनाएंगे। यह निर्णय गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन म.प्र. की वर्चुअल मासिक बैठक मे लिया गया। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन बैठक में शासन से 1 जुलाई 2019 से पांच प्रतिशत और 1 जनवरी 2020 से चार प्रतिशत कुल नौ प्रतिशत महंगाई भत्ता, 1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2008 तक 32 माह का छटवें वेतनमान का एरियर, 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक 27 माह सातवें वेतनमान का एरियर का शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई। बैठक में यह भी मांग रखी गई कि कोरोना महामारी को देखते हुए पेंशनरों का निजी अस्पतालों में कैशलैस उपचार कराने के लिए शीघ्र सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए। अंत में कोरोन काल में स्वर्गवासी हुए पेंशनर गंगाधर खंडालकर एवं पांडुरंग मुसलगांवकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में जगमोहन सक्सेना, शिवाजीराव दौण्ड, भगवानदास यादव, अशोक बक्षी, मदनलाल वर्मा, गिरीश श्रीवास्तव, वी.के. सक्सेना, फतेह सिंह शितोले, अनंत गंगाजलि वाले सहित अन्य सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति नहीं होगी अनिवार्य

कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के संचालन के दिशा-निर्देश जारी

भोपाल, (प्रसं)। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभ एवं संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करने के लिए निर्देश दिए थे। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुक्रम में यह निर्देश जारी किए गए हैं।

बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 18 दिसंबर से स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित रहेंगे। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति माता-पिता, अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगी। माता-पिता, अभिभावकों द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। आवासीय विद्यालय डे स्कूल के रूप में खोले जा सकेंगे। विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही परिवहन सुविधा में वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और वाहनों को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति शत-प्रतिशत होगी। विद्यालय में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद आदि गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

आंदोलन के लिए तैयार हो रहा प्रदेश का खेल शिक्षक संघ

भर्ती की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री डंग को दिया ज्ञापन

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल

मप्र में खेल शिक्षकों की भर्ती को लेकर रोष चरम पर है। पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी का दंश झेल रहे खेल शिक्षक सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से दुखी हैं। सरकारें बदलीं लेकिन खेल शिक्षक संघ मी मांग पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। इसी उपेक्षा से नाराज खेल शिक्षक अब प्रदेश की सड़कों पर उग्र आंदोलन की तैयारी में जुट गया है।

बीपीएड संघ मध्यप्रदेश के संभाग अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि इससे पहले कई बार इस विषय पर सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर मांग की जाती रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हालात बद से बद्तर होते जा रहे हैं। पढ़ा लिखा खेल शिक्षक अब मजदूरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूं तो सरकारें स्कूली स्तर पर खेल को लेकर रूपरेखा बनाती रही है, लेकिन स्कूलों में खेल शिक्षकों की भर्ती को लेकर गुरेज करती रही है। संघ की मांग है कि खेल शिक्षक की भर्ती निकाली जाना चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही प्राथमिकता दी जाना चाहिए।

मंत्री को समस्या से अवगत कराया

खेल शिक्षक की भर्ती मांग को लेकर संघ के पदाधिकारियों ने केबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के सीतामऊ आगमन पर उनसे मुलाकात की है। मंत्री को अवगत कराया गया है कि कि मध्यप्रदेश में 2008-09 के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में खेल शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है और न ही खेल शिक्षक को अतिथि के रूप में रखा गया है। यह हालात जब हैं जबकि 2018 मध्यप्रदेश शासन के राज्यपत्र में खेल शिक्षक भर्ती का उल्लेख किया गया है।

भोपाल में होगा निर्णय

संजय चौहान ने कहा कि बीपीएड संघ मप्र प्रदेश के जिला, तहसील, ब्लाक स्तर पर धरना प्रर्दशन करेगा। इसके अलावा भूख हड़ताल जैसा आंदोलन करेगा। इसके लिए भोपाल में रणनीति तैयार की जाएगी।

हाईस्कूल, हायर सेकंडरी की कक्षाएं अब नियमित रूप से लगेंगी

विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से प्रबंधन का जिम्मा स्कूलों पर, अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थियों को बुलाया जा सकेगा स्कूल

भोपाल (ब्यूरो)। निजी स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी की कक्षाएं पूरे समय के लिए नियमित रूप से लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के पालन (भीड़ प्रबंधन) की जिम्मेवारी स्कूलों पर छोड़ी है। स्कूल प्रबंधन को एक बार में सीमित संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बुलाना होगा। भले ही इसके लिए स्कूलों को दो-तीन शिफ्ट में कक्षाएं लगानी पड़ें। हालांकि विद्यार्थियों को स्कूल बुलाना

अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसा करने से पहले स्कूल प्रबंधन को बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की सहमति लेनी होगी, जो पूरे सत्र (2020-21) के लिए मान्य होगी। यह व्यवस्था सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समान रूप से लागू रहेगी।

निजी स्कूल संचालक स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री और स्कूल संचालकों के बीच तीन बार की बैठक भी हो चुकी है। एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल ने मंगलवार को प्रदेश में ऑनलाइन कक्षाएं बंद रखने का आह्वान किया था। हालांकि राजधानी में एसोसिएशन के आह्वान का

असर देखने को नहीं मिला, पर सरकार ने शाम को नए निर्देश जारी कर दिए। जिसके तहत कक्षाएं लगाने के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेवारी स्कूलों की होगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आना चाहते हैं। उन्हें स्कूल ऑनलाइन पढ़ाएंगे।

निर्देशों में यह भी ...

- पहली से आठवीं तक कक्षाएं 31 दिसंबर तक पूरी तरह से बंद रहेंगी।
- नौवीं और 11वीं की कक्षाएं स्कूलों में कक्षों की उपलब्धता के आधार पर खोली जाएंगी। प्राचार्य इस संबंध में फैसला लेंगे।
- प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ शत प्रतिशत उपस्थित रहेगा।
- छात्रावास और आवासीय स्कूल नहीं खोले जाएंगे। हालांकि आवासीय स्कूल डे-स्कूल के रूप में खोले जा सकेंगे।
- स्कूल में प्रार्थना, खेलकूद, स्वीमिंग पूल सहित अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
- स्कूल परिवहन व्यवस्था करते हैं, तो बसों या अन्य वाहनों में शारीरिक दूरी का पालन कराना अनिवार्य होगा। वाहन को सोडियम हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइज कराना होगा।

नए सत्र से पहले आएगा उच्च शिक्षा आयोग

नई दिल्ली (ब्यूरो)। मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को छोड़ पूरी उच्च शिक्षा अब भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के दायरे में होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित इस आयोग के गठन की तैयारी तेज हो गई है। शिक्षा मंत्रालय ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले ही इसके गठन की योजना बनाई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसी सभी उच्च शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं अब इसके अधीन काम करेंगी।

खास बात यह है कि इस आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से पहले भी किया था। उच्च शिक्षण संस्थानों की आपत्ति के बाद इसे टाल दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी जरूरत बताई गई जिसके बाद

शिक्षा

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आयोग के गठन का है प्रस्ताव**
- **पूरी उच्च शिक्षा चार अलग-अलग अंगों द्वारा संचालित होगी**

शिक्षा मंत्रालय ने तैयारी तेज की है। वैसे भी मंत्रालय ने नीति के अमल का रोडमैप तैयार किया है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की मानें तो नए शैक्षणिक सत्र से प्रस्तावित आयोग अपना काम-काज संभाल लेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे ऐसे आयोग के गठन को मंजूरी तब दी गई, जब देश में उच्च शिक्षा अलग-अलग नियामकों के द्वारा संचालित होती हैं। इनमें विश्वविद्यालयों और कालेजों के नियामक और वित्तीय मदद के लिए यूजीसी, उच्च शिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (नैक), शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीटीई और तकनीकी शिक्षा के लिए एआइसीटीई काम कर रहा है। लेकिन भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के बाद अब पूरी उच्च शिक्षा चार अलग-अलग अंगों द्वारा संचालित होगी। जिसमें नियामक के रूप में अब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद काम करेगा। इसके दायरे में अब शिक्षक शिक्षा भी रहेगी। वहीं मूल्यांकन और ग्रेडिंग का काम नैक देखेगा। जो संस्थानों की गुणवत्ता को मजबूत बनाने का काम करेगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का तीसरा अंग उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद होगा, जो सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय मदद देने का काम करेगा। इसका चौथा अंग सामान्य शिक्षा परिषद होगा, जिसमें जो पढ़ाई के बाद छात्र किस क्षेत्र में जाएगा, उसके फ्रेमवर्क को लेकर काम करेगा।

आइआइटी-गुवाहाटी के छात्रों ने फसलों के प्रबंधन में मदद के लिए बनाया एप

गुवाहाटी (एजेंसी)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) गुवाहाटी के छात्रों और एनआइटी सिल्चर तथा डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों ने किसानों को उनकी फसलों के प्रबंधन में मदद करने के लिए एक बहुभाषी एप एगस्पीक तैयार किया है। आइआइटी गुवाहाटी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कृत्रिम बुद्धिमता (एआइ) के जरिए किसानों को उनके उत्पादों के बारे में लक्ष्य तैयार करने के लिए यह एप तैयार किया गया है। अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर एप के जरिए किसान कृषि संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन कर सकते हैं। आइआइटी के निदेशक प्रोफेसर टीजी सीताराम ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे छात्र देश के किसानों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी लाने पर काम कर रहे हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एगस्पीक में बहुभाषा की सुविधा है और असमिया भाषा का भी इसमें विकल्प है। इस एप में फसल के संबंध में 20 स्थानीय कारकों पर विचार किया गया है। जैसे कि तापमान, बारिश, सूर्य दिखाई देने का समय, मृदा की स्थिति समेत अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए किसानों को फसल से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के लिए पहले ही यह सचेत कर देगा। इससे किसान अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे।

हायर सेकंडरी की कक्षाएं अब नियमित रूप से लगेंगी

संख्या के हिसाब से प्रबंधन का जिम्मा स्कूलों पर, अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थियों को बुलाया जा सकेगा स्कूल

कैंपस

अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसा करने से पहले स्कूल प्रबंधन को बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की सहमति लेनी होगी, जो पूरे सत्र (2020-21) के लिए मान्य होगी। यह व्यवस्था सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समान रूप से लागू रहेगी।

निजी स्कूल संचालक स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री और स्कूल संचालकों के बीच तीन दौर की बैठक भी हो चुकी है। एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल ने मंगलवार को प्रदेश में ऑनलाइन कक्षाएं बंद रखने का आह्वान किया था। हालांकि राजधानी में एसोसिएशन के आह्वान का

असर देखने को नहीं मिला, पर सरकार ने शाम को नए निर्देश जारी कर दिए। जिसके तहत कक्षाएं लगाने के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी स्कूलों की होगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आना चाहते हैं। उन्हें स्कूल ऑनलाइन पढ़ाएंगे।

निर्देशों में यह भी ...

- पहली से आठवीं तक कक्षाएं 31 दिसंबर तक पूरी तरह से बंद रहेंगी।
- नौवीं और 11वीं की कक्षाएं स्कूलों में कक्षों की उपलब्धता के आधार पर खोली जाएंगी। प्राचार्य इस संबंध में फैसला लेंगे।
- प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ शत प्रतिशत उपस्थित रहेगा।
- छात्रावास और आवासीय स्कूल नहीं खोले जाएंगे। हालांकि आवासीय स्कूल डे-स्कूल के रूप में खोले जा सकेंगे।
- स्कूल में प्रार्थना, खेलकूद, स्वीमिंग पूल सहित अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
- स्कूल परिवहन व्यवस्था करते हैं, तो बसों या अन्य वाहनों में शारीरिक दूरी का पालन कराना अनिवार्य होगा। वाहन को सोडियम हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइज कराना होगा।

स्पेशल सप्लीमेंट्री-एटीकेटी के पेपर 17 को होंगे अपलोड

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमित होने से परीक्षा से वंचित रहने और फेल हो चुके विद्यार्थियों को साल बचाने के लिए एक ओर मौका दिया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने यूजी फाइनल ईयर और पीजी फाइनल सेमेस्टर के लिए स्पेशल सप्लीमेंट्री और एटीकेटी परीक्षा रखी है। ओपन बुक पद्धति से परीक्षा संचालित होगी, जिसमें करीब आठ हजार से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। खास बात यह है कि विवि ने 17 दिसंबर को पेपर वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला किया है। विद्यार्थियों को पांच दिन के भीतर जवाब लिखकर उत्तर पुस्तिका जमा करवानी होगी।

उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद सितंबर-अक्टूबर में विश्वविद्यालय ने ओपन बुक पद्धति से यूजी-पीजी कोर्स की परीक्षा करवाई थी। बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएसडब्ल्यू, बीए मास कम्युनिकेशन फाइनल ईयर के करीब 44 हजार और एमए, एमकॉम, एमएससी समेत अन्य पीजी फाइनल सेमेस्टर के 11 हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 10 फीसद विद्यार्थी संक्रमित होने और कंटेनमेंट इलाकों में रहने के चलते परीक्षा नहीं दे पाए। विभाग ने इन विद्यार्थियों का साल बचाने के लिए स्पेशल परीक्षा कराने का फैसला किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 11 दिसंबर से आवेदन बुलवाए हैं। कॉलेजों को भी अपने-अपने विद्यार्थियों से संपर्क कर परीक्षा फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी का कहना है कि 17 दिसंबर से ओपन बुक पद्धति से परीक्षा करवाएंगे। पेपर अपलोड होने के बाद विद्यार्थियों को संग्रहण केंद्र में उत्तरपुस्तिका जमा करनी होगी। रिजल्ट भी महीनेभर में घोषित करेंगे।

बीएड की परीक्षा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में

बीएड कोर्स की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा में करीब छह महीने देरी हो चुकी है। अधिकारियों ने तय किया है कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा भी ओपन बुक पद्धति से करवाई जाएगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में परीक्षा रखी है। अभी तारीख तय नहीं हुई है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की गाइड लाइन

स्कूलों में नहीं होगी प्रार्थना अभिभावकों की अनुमति जरूरी

भोपाल निप्र

मध्यप्रदेश में 18 दिसंबर से शुरू हो रहीं कक्षा दसवीं और बारहवीं की कक्षा के लिए प्रार्थना आदि नहीं होगी। बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। एक बार अनुमति देने के बाद यह पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। इस संबंध में मंगलवार दोपहर में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने गाइड लाइन भी जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद आठवीं तक की कक्षाओं पर फैसला लिया जाएगा।

यह है गाइड लाइन में

बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय के लिए संचालित रहेंगे।

विद्यार्थियों को इस तरह बुलाया जाएगा कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक साथ अधिक ना हो, ताकि गाइड लाइन का पालन किया जा सके।

विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यह माता-पिता अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगा।

माता-पिता अभिभावकों द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी।

प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ पूरी तरह उपस्थित रहेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग सिलेबस कम नहीं करेगा, दो महीने में करना होगा पूरा

भोपाल (ब्यूरो)। उच्च शिक्षा विभाग की कक्षाएं एक जनवरी से नियमित तौर पर लगनी शुरू हो जाएंगी। इसी बीच विद्यार्थियों के सामने अब एक नई चुनौती आ गई है। उन्हें आठ महीने का सिलेबस अब सिर्फ दो महीने में पूरा करना होगा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सिलेबस में कटौती नहीं की जाएगी। सिलेबस में कटौती या बढ़ोतरी करना काफी लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में ही दो से तीन महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में हर साल की तरह विद्यार्थियों को पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। गौरतलब है कि इस बार यूजी कक्षाओं में करीब चार लाख 37 हजार जबकि पीजी में एक लाख 30 हजार विद्यार्थी हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक जनवरी से पचास फीसद विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है। कोरोना की वजह से पिछले आठ महीने से कॉलेज बंद हैं। इस संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा चंद्रशेखर बालिंबे का कहना है कि सिलेबस बढ़ाने या कम करने की प्रक्रिया बेहद लंबी है। जब कोई सिलेबस में से तथ्य कम करने या घटाने होते हैं तो पूरी प्रक्रिया एक शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले करनी होती है। इसे अध्ययन मंडल तक भेजना होता है। ऐसे में यदि आधे से ज्यादा सत्र बीतने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई तो परीक्षा का समय आ जाएगा लेकिन नया सिलेबस नहीं बन पाएगा।

जुलाई से शुरू होता था सत्र : हर साल एक जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाता था। फरवरी के अंत तक पढ़ाई कराकर मार्च-अप्रैल में परीक्षा आयोजित करा ली जाती थी।

सहायक प्राध्यापकों की भर्ती को लेकर डीन और मेडिकल टीचर्स में ठनी

सच प्रतिनिधि ॥ भोपाल

गांधी मेडिकल कॉलेज में की गई सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में आंतरिक उम्मीदवारों के साथ भेदभाव से नाराज गांधी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षक आंदोलन की राह पर हैं। भर्ती नियम को लेकर डीन डॉ. अरुणा कुमार और मेडिकल टीचर्स के बीच ठन गई है । डीन पर आरोप है कि सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में जानबूझकर कॉलेज में पहले से काम कर रहे पात्र प्रत्याशियों (इंटरनल कैंटीडेट) को अवसर नहीं दिया गया और बाहरी प्रत्याशियों का चयन कर लिया। मामला चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग तक पहुंच गया है। निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की तैयारी है।

इस संबंध में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की कल आहूत बैठक में इंटरनल कैंडीडेट के साथ हुए अन्याय का विरोध करते हुए डीन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मेडिकल टीचर्स का कहना है कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के समय ही डीन को अवगत करा दिया गया था कि आंतरिक उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए और उन्होंने इसका भरोसा भी दिया था लेकिन सभी 20 पदों पर बाहरी उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है यह मंजूर नहीं है।

विदित है कि इसके पूर्व गांधी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट्स के पदों की भर्ती को लेकर भी विवाद हो चुका है। इस भर्ती में भी चयन प्रक्रिया से बाहर किए गए आवेदकों ने डीन पर अनियमितताओं और मनमर्जी से काम करने के आरोप लगाए थे।

गांधी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में ऐसे डेमांस्ट्रेटर हैं जिन्होंने डीएम की डिग्री हासिल की हुई है लेकिन भर्ती नियमों की अपने हिसाब से व्याख्या कर उन्हें इस भर्ती से बाहर रखा गया है।

सीएमटीए के सचिव डॉ. राकेश मालवीय के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा विभाग अथवा स्वशासी कॉलेज के सेवा भर्ती नियम के अनुसार यदि संस्थान में सहायक प्राध्यापक के पद रिक्त होने अथवा नए पद मंजूर किए गए हैं तो उन पर नए लोगों की भर्ती के पहले आंतरिक विज्ञप्ति निकाली जाकर संस्था में पहले से कार्यरत पात्र डेमांस्ट्रेटर को वरीयता देने का प्रावधान है लेकिन हाल ही में की गई भर्ती में इस नियम का पालन नहीं किया गया है।

डीन की कार्यप्रणाली से असंतोष, निंदा प्रस्ताव पारित

डीन कुमार की कार्यप्रणाली से अस्पताल के कनिष्ठ और वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ ही कर्मचारियों में भी आक्रोश है। इसके पूर्व डीएमसी के कर्मचारी भी डीन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उनका आरोप था कि डीन किसी से मिलती नहीं है, कर्मचारी विभागीय फाइलें लेकर उनके पास जाते हैं तो उन्हें घंटों बैठाकर रखा जाता है। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के इस मामले को लेकर कल गांधी मेडिकल कॉलेज में आहूत मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की बैठक में डीन डॉ. अरुणा कुमार की कार्यप्रणाली के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।

विभागीय मंत्री से आज होगी मुलाकात

सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में आंतरिक उम्मीदवारों के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात कर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराएंगे।

र्ड पी जी. इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विस प्रा. लि. राजौद भानपुर साइपास रोड, भोपाल-46 2037 (म.प्र.) से मुद्रित एवं प्लॉट नं. 192, एरोसिटी टॉवर, जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल से प्रकाशित।

वेबसाइट हुई लॉक, कई छात्रों के दस्तावेज नहीं हो सके जमा

सच प्रतिनिधि || भोपाल

स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश ले चुके कई छात्र-छात्राओं के दस्तावेज अंतिम तारीख तक भी जमा नहीं हो सके हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इन विद्यार्थियों को 12 दिसंबर तक का समय दिया था। इसके बाद विभाग ने वेबसाइट को लॉक कर दिया है। ऐसे में विद्यार्थी परेशान हैं कि उनके दाखिले निरस्त न हो जाएं। छात्र-छात्राओं ने विभाग से दस्तावेज जमा करने के लिए एक और मोहलत देने की मांग की है।

विभाग ने यूजी-पीजी में एडमिशन ले चुके छात्रों को 12 दिसंबर तक का दिया था समय

प्रदेश में फैले कोरोना वायरस के कारण विभाग ने विद्यार्थियों को बिना दस्तावेज (टीसी, माइग्रेशन एवं अन्य आवश्यक कागजात) के दाखिला लेने की छूट दी थी। एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्र-छात्राओं को दस्तावेज जमा करने के लिए 12 दिसंबर तक का समय दिया गया था। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट में 30 नवंबर अंतिम तारीख थी।

उच्च शिक्षा विभाग ने ऐसे छात्र-छात्राओं जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है या किसी कारण से वे दस्तावेज (टीसी, माइग्रेशन एवं अन्य आवश्यक कागजात) जमा नहीं कर सकते हैं, उनके एडमिशन वचन-पत्र के आधार मान्य करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद कई विद्यार्थियों ने न तो वचन-पत्र जमा किया और न ही दस्तावेज जमा किए। ये विद्यार्थी अब रोजाना कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं। प्रदेश में ऐसे छात्र-छात्राओं की संख्या करीब 20 हजार है। प्रदेश में संचालित सभी 1405 कॉलेजों में 15 से 20 छात्र-छात्राएं रोजाना पहुंच रहे हैं।

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने डीपीआई घेरा

सच प्रतिनिधि || भोपाल

उच्च माध्यमिक भर्ती और माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वालिफाई हुए अभ्यर्थियों ने जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश भर से करीब 500 अभ्यर्थियों शामिल हुए। अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती के लिए आज शाम तक पोर्टल अपडेट कर प्रक्रिया शुरू की जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि मंत्री के आदेश के बाद भी डीपीआई के अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

परीक्षा में क्वालिफाई हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 20 अप्रैल से शुरू किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू की जाना थी। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम चयन सूची व वेटिंग लिस्ट जारी होगी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उच्च माध्यमिक के 15000 पदों पर भर्ती होना है। इसमें से अनारक्षित वर्ग के 3789 पद हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 1393 पद आरक्षित किए गए हैं।

ज्ञात हो कि संविदा शिक्षक भर्ती-2005 से शुरू हुई। इससे पहले सीधी भर्ती होती थी। सन् 2001 में सीधी भर्ती से 36 हजार पद भरे गए थे। सन् 2003 में 40 हजार पदों पर भर्ती की गई। इसके बाद 2005 में पहली बार 25 हजार पदों के लिए संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा व्यापमं द्वारा ली गई।

परिणाम के बाद 2006-07 में भर्ती हुई। फिर सन् 2008-09 में 30 हजार पदों के लिए संविदा परीक्षा हुई। सन् 2009 में भर्ती हुई। इसके बाद 2013 में 42 हजार पदों के लिए संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। भर्ती प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई।

फरवरी 2019 में हुई थी परीक्षा

छह साल के लंबे इंतजार के बाद सरकारी स्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया सितंबर 2018 में शुरू की गई थी एवं फरवरी 2019 में परीक्षा ली गई थी, लेकिन अब तक अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं हो सकी है।

तीन साल पहले शुरू हुए मेडिकल कॉलेज में न स्टाफ, न संसाधन

नईदुनिया अभियान
जिंदगी हारते मासूम

शहडोल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहडोल संभाग को मेडिकल कॉलेज की सौगात तो तीन साल पहले मिल गई लेकिन यहां की स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। यहां संसाधन की कमी तो है ही, अब तक नर्सिंग और सहयोगी स्टाफ की भर्ती नहीं हो पाई है। पिछले नौ माह से यहां केवल कोरोना मरीजों को ही भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा किसी अन्य बीमारी के मरीजों का इलाज यहां नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि मेडिकल कॉलेज तो शुरू हो गया लेकिन इसका सीधा लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है।

शहडोल। जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज। ● **फाइल फोटो**

वेतन-भवन में करोड़ों रुपये का खर्च : मेडिकल कॉलेज की शुरुआत वर्ष 2018 में हो गई थी। करोड़ों रुपये का भवन बना और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के वेतन पर भी करोड़ों रुपये खर्च हो गए लेकिन फायदा ज्यादा कुछ नहीं हुआ।

मशीनें नहीं लगीं, ऑपरेशन थिएटर भी तैयार नहीं : मेडिकल कॉलेज में महिला रोग, प्रसूति व बच्चों के रोग से संबंधित ओपीडी को शुरू होने में वक्त लगेगा। अभी यहां मशीनें सेट नहीं हो पाई हैं। ऑपरेशन थिएटर तैयार होने में भी वक्त लगेगा। प्रसूति वार्ड में लगने वाली जरूरी मशीनों का ऑर्डर हो गया है जिनके आने में अभी वक्त है। ओटी लाइट लग चुकी है पर स्लाइडिंग वाले गेट नहीं लग पाए हैं।

यह है मेडिकल कॉलेज की स्थिति

- मेडिकल कॉलेज की लागत 350 करोड़ रुपये है।
- 66 डॉक्टर्स सिर्फ 100 छात्रों को पढ़ाने के लिए हैं। 59 नर्स कोरोना के इलाज के लिए अस्थायी रूप से भर्ती की गई हैं।
- कोरोना के पहले ओपीडी शुरू हुई तो सिर्फ नाक, कान, गला, मेडिसिन, त्वचा रोग के मरीजों को देखा जा रहा था।
- मरीजों को न तो यहां से दवाएं मिल पा रही थीं और नहीं जांच हो पा रही थी।
- नाक, कान, गला के मरीजों के लिए मशीनें अभी नहीं मंगाई गई हैं।

> जनवरी 2021 के बाद कुछ सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। नर्सिंग स्टॉफ के साथ सपोर्टिंग स्टॉफ भी रखा जाना है। प्रयास है कि सब काम जल्दी हो, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। अभी तो जनरल ओपीडी और कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है।
>
> **-डॉ. नागेंद्र सिंह**
> अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज शहडोल

घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ने से पांच प्रतिशत बच्चों की आंखें हुई कमजोर

ग्वालियर, न.सं.

कोरोना संक्रमण के कारण मार्च माह से स्कूल बंद हैं। इन प्रायमरी और मिडिल स्कूलों को बंद हुए आज नौ माह से अधिक का समय हो गया है। बच्चों की पढ़ाई लेपटॉप, मोबाइल और कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन हो रही है।

ऑनलाइन पढ़ने के कारण पांच प्रतिशत बच्चों की आंखे कमजोर हो गई हैं। जिन बच्चों को पहले से चश्मा लगा था उनका नम्बर बढ़ गया है। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बच्चों के सिर में दर्द और आंखों में खुजली होने की समस्याएं आ रही हैं। चिकित्सकों के पास भी पहले

की अपेक्षा अब आँखों के मरीज अधिक आ रहे हैं। आने वाले इन मरीजों में बच्चों की संख्या अधिक है। स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो और बच्चे सुरक्षित रहें इसलिए बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही है। मगर इस पढ़ाई का नुकसान यह हो रहा है कि लगातार पढ़ने से बच्चों की आंखे कमजोर हो गई हैं या फिर चश्मे का नम्बर बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण पलकों का कम झपकना और आंखों का सूखना है। वहीं अभिभावकों का भी कहना है कि जब बच्चे शादी-समारोह और बाजारों में जा रहे हैं तो कोविड नियमों का पालन करते हुए स्कूल भी जा सकते हैं। वहीं शहर में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। कक्षा 10 औ 12 की कक्षाएं 18 दिसंबर से नियमित शुरू होने जा रही है। ऐसे में अभिभावकों और स्कूल संचालकों का कहना है कि कक्षा 6 से 8 तक की भी कक्षाएं शुरू की जाएं।

इनका कहना है

'पहले पौं आंखों अब आंखों से जुड़े केस अधिक आ रहे हैं। इसमें कम उम्र की बच्चों की संख्या अधिक है। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बच्चों को आंखों में जलन, खुजली और सरदर्द की समस्याएं आ रही हैं। ऐसा इसलिए है कि ऑनलाइन पढ़ने के कारण बच्चों की पलकें कम झपकती हैं और आंखे ड्राय हो जाती हैं।'

डॉ. गिरीश चतुर्वेदी, नेत्र रोग विशेषज्ञ

'मेरा बच्चा ऐबनेजर स्कूल कक्षा सात में पढ़ता है। ऑनलाइन पढ़ने से बच्चों की आंखे खराब हो रही है। ऐतिहायत बरतते हुए अब स्कूल खुल जाने चाहिए। घर में रखकर बच्चे परेशान भी अधिक कर रहे है।'

नीरज शर्मा, अभिभावक

'मेरा बच्चा एबनेजर स्कूल कक्षा छठवीं में पढ़ता है। जब तक क्लास चलती है तब तक बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है। मेरे बच्चे का चश्मे का नंबर भी बढ़ गया है। अब कोविड नियमों का पालन करते हुए स्कूल खुल जाने चाहिए, इससे बच्चों की पढ़ाई और अच्छी होगी व माहौल भी बदलेगा।'

कल्पना एस. तोमर, अभिभावक

सरदार पटेल स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स पसूईंग ग्रेजुएशन 2020

विवरणः बडी 4 स्टडी इंडिया फॉउंडेशन स्नातक के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृति आवेदन आमंत्रित करता है। यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम योग्य किन्तु उच्च शिक्षा से वंचित छात्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से बनाया गया है।

मानदंडः किसी मान्यता प्राप्त विवि संस्थान से तीन वर्षीय स्नातक प्रोग्राम किसी भी शाखा में के प्रथम, द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन खुले हैं। किन्तु आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय आईएनआर 6 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।

इनामः चयनित छात्रों को 15,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

अंतिम तिथिः 31.12.2020

आवेदन : ऑनलाइन आवेदन करें

लिंकः www.b4s.in/Sach/SPS1

सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को निर्देश

बाल गृह के बच्चों को 30 दिन में फ्री पढ़ाई सुविधा दें: सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी | नई दिल्ली

देशभर में चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम में रह रहे बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकारों को बच्चों को स्टेशनरी, किताबें व अन्य सुविधाएं 30 दिन के अंदर मुहैया कराने को कहा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी की पीठ ने बच्चों की पढ़ाई बाधित होने को लेकर ये अहम दिशा-निर्देश जारी किए। एमिकस क्यूरी (कोर्ट मित्र) गौरव अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम में रहने वाले कुल 2 लाख 27 हजार 511 बच्चों में से एक लाख 45 हजार 788 बच्चों को उनके अभिभावकों के पास वापस भेजा गया है। चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को बच्चों की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए।

ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। जस्टिस राव ने कहा कि राज्य सरकारें प्रत्येक 22 से 24 छात्रों पर एक शिक्षक नियुक्त करे। बच्चों की आनलाइन कक्षाओं की भी व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए राज्य सरकारें जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएं। बच्चों को स्टेशनरी, किताबें व अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं।

आर्थिक तंगी है तो बच्चे को 2000 रुपए दें पढ़ाई के लिए

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि जिला चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन यूनिट अभिभावकों के पास भेजे गए बच्चों की प्रोग्रेस की जांच करेगी। वह यह देखेगी कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं? अगर किसी परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से बच्चे को स्कूल भेजने में अभिभावक सक्षम नहीं हैं तो ऐसे परिवारों को 2 हजार रुपए आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएं। यह सुनिश्चित करें कि यह पैसा सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च हो।

10वीं-12वीं के स्कूल खुलने के फैसले के बाद नए निर्देश

स्कूल आने की बाध्यता नहीं, जो आएंगे उनके लिए माता-पिता की सहमति जरूरी

स्कूल संचालक माने, आज प्रदर्शन स्थगित

भोपाल| 10वीं-12वीं की कक्षाएं लगाने के फैसले के एक दिन बाद मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बारे में नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इसके अनुसार, स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। उनका आना अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगा। एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। सरकार के फैसले के बाद बुधवार को प्रदर्शन का अल्टीमेटम देने वाले स्कूल संचालकों ने भी अपना रुख बदलते हुए आंदोलन स्थगित कर दिया। 9वीं-11वीं के स्कूलों का मामला प्राचार्यों पर ही छोड़ा गया है। इस बारे में नए निर्देश में कहा गया है कि 9वीं-11वीं विद्यार्थियों के स्कूलों में दर्ज संख्या एवं उपलब्ध कक्षों के लिहाज से प्राचार्य ही स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालक के बारे में निर्णय ले सकेंगे।

प्रार्थना और खेलकूद नहीं

- हॉस्टल और आवासीय स्कूल खोलने की अनुमति नहीं होगी।
- स्कूलों में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद प्रतिबंधित रहेंगे।
- जिन स्कूलों में बसें चलाई जाएंगी, उनमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना होगा। वाहनों में सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइजेशन जरूरी होगा।

नवोदय प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन अब 29 तक भरे होंगे

-निज प्रतिनिधि-

गुना। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वी और 9 वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। कक्षा पांचवी में अध्ययनरत विद्यार्थी अब कक्षा छठवी के लिए अब 29 दिसंबर और कक्षा आठवीं में अध्ययनरत विद्यार्थी कक्षा नवमी के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नवोदय कर्मचारी कल्याण संघ के राष्ट्रीय प्रेस सचिव प्रशान्त चंसोरिया ने बताया कि संगठन ने पत्र भेजकर आयुक्त को जिले में आ रही समस्यों से अवगत कराया था। जिस पर विचार कर नवोदय विद्यालय समिति आयुक्त ने विद्यार्थियों के हितों में अंतिम तिथि को बढ़ाया है। जिससे छात्रों ने राहत की सांस ली है।

एक लाख वेतन लेने के बाद भी नहीं पढ़ाते प्राध्यापक

एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपकर की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग

-निज प्रतिनिधि-

गुना। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग एनएसयूआई ने की है। इसको लेकर एक ज्ञापन मंगलवार को कॉलेज प्राचार्य बीपी तिवारी को सौपा है। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि कॉलेज के कई प्राध्यापकों का वेतन एक लाख या उससे भी ज्यादा है। उसके बाद भी उनकी रुचि बच्चों को पढ़ाने में नहीं है। जहां वह गप्पे हांकने में लगे रहते है तो चाय-भोजन के नाम पर घंटों तक गायब रहते है। प्राध्यापकों द्वारा महाविद्यालय की समय सारणी का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रदेश सचिव विशाल रघुवंशी का कहना था कि मुख्यतः रसायन विभाग में समय सारिणी के अनुसार नहीं चलता है। समय से एक घंटे पूर्व डिपार्टमेंट में प्रोफेसर आर ही हैं।

प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यकर्ता।

छात्र हो रहे है परेशान

ज्ञापन में संगठन के प्रदेश महासचिव व पूर्व कॉलेज अध्यक्ष गौरव रघुवंशी ने बताया कि कॉलेज में पढ़ाई न होने से छात्र परेशान हो रहे है। साथ ही पढ़ाई का स्तर भी गिर रहा है। भौतिकी, जूलोजी सहित अन्य विभाग भी समय पर नहीं खुलते तथा समय से पहले ही बंद हो जाते हैं। अधिकांश प्रोफेसर्स चाय पीने के नाम पर एक-एक घंटे गायब रहते हैं। जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ज्ञापन देते समय एनएसयूआई जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, कॉलेज अध्यक्ष के साथ प्रदेश सचिव मनीष रघुवंशी, आशीष जकोलिया, मोनू यादव आदि मौजूद थे।

निजी स्कूलों ने 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई तो जिला समिति करेगी निर्णय

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालय फीस अधिनियम 2017 के नियम 2 दिसंबर 2020 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिए हैं। अधिनियम बनने के तीन साल बाद नियम बन पाए हैं। नियमों के अनुसार निजी स्कूल पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे कम फीस वृद्धि करने के लिए सक्षम होंगे। यदि निजी स्कूल ने 10 प्रतिशत से अधिक 15 प्रतिशत तक फीस वृद्धि की है तो उस पर जिला समिति द्वारा 15 दिन में निर्णय लिया जाएगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया कि यदि 15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की गई है तो उस पर राज्य समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

एनटीए का ऐलान • आवेदन 15 जनवरी तक

जेईई मेन्स अगले साल से 4 बार पहली परीक्षा 22 फरवरी को

भास्कर न्यूज | कोटा

देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स-2021 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को स्थिति स्पष्ट कर दी है। वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार अब साल में 4 बार जेईई-मेन्स होगी। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल व मई में होगी।

पहली परीक्षा 22 से 25 फरवरी के बीच होगी। इसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यह परीक्षा बदले हुए पैटर्न में भी कराई जाएगी। कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूज ने बताया कि देश-विदेश के 329 परीक्षा शहरों में जेईई-मेन्स दो पारियों में आयोजित की जाएगी।

पैटर्न में ये बड़े बदलाव

▪ 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। ▪ पेपर दो भागों में विभक्त होगा। फिजिक्स, कैमिस्ट्री व मैथ्स में सेक्शन ए और सेक्शन बी होंगे। सेक्शन ए में हर विषय में 20 बहुविकल्पीय सवाल दिए जाएंगे। ▪ सेक्शन बी में न्यूमेरिकल वैल्यु बेस्ड 10 सवाल दिए जाएंगे। ▪ इन 10 में से कोई 5 सवाल स्टूडेंट्स को हल करने होंगे। ▪ कुल 90 में से 75 प्रश्न हल करने का मौका दिया जाएगा। ▪ हर प्रश्न 4 अंकों का होगा। ▪ बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर देने पर 4 अंक दिए जाएंगे। गलत पर नेगेटिव मार्किंग।

पीईबी ने डिप्लोमा इन हसबेंडरी एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट जारी किए

भोपाल। मप्र प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने डिप्लोमा इन हसबेंडरी एंट्रेंस टेस्ट-2020 (डाहेट)का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार रिजल्ट देखने के लिए एमपी पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। डाहेट-2020 का आयोजन 5 से 7 नवंबर 2020 तक आयोजित किया गया था। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विवि जबलपुर द्वारा प्रदेश के पांच वेटरनरी पॉलीटेक्निक कॉलेजों में द्विवर्षीय पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 315 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था।

परिणाम

इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक छात्रों का ऑनलाइन प्रशिक्षण 18 से

भोपाल। इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक छात्रों को आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस जैसे आधुनिक कोर्स को समझने और इसकी बारीकियों को सीखने का मौका तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा विभाग और माइक्रोसॉफ्ट के संयुक्त तत्वावधान में 18 एवं 19 दिसंबर को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। यह प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। इंजीनियरिंग के छात्र 18 और पॉलीटेक्निक के छात्र 19 दिसंबर को इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे।

स्किल

गाइडलाइन का करना होगा पालन, नहीं होगी प्रार्थना, अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य

निजी स्कूलों का बंद बेअसर, शिक्षा विभाग ने जारी की स्कूल खोलने की गाइडलाइन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में असंतुष्ट निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण कार्य बंद रखने का ऐलान मंगलवार को बेअसर रहा। अधिकतर सीबीएसई स्कूलों में प्रतिदिन की तरह ऑनलाइन क्लासें चलाई गई। इधर, स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी कारवाई जारी रखते हुए स्कूलों को खोलने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

स्कूलों को सुरक्षा संबंधी एसओपी-गाइडलाइन का पालन करना होगा। 18 दिसंबर से शुरू हो रहीं कक्षा दसवीं और बारहवीं की क्लास के लिए प्रार्थना आदि नहीं होंगी। स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यह अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगा। माता-पिता या अभिभावकों द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। बता दें कि प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर सीबीएसई स्कूल संचालकों और सरकार के मध्य बातचीत के बावजूद मंगलवार तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।

सीबीएसई स्कूल संचालकों और सरकार के मध्य नहीं बनी बात

इन नियमों के साथ लगेंगे स्कूल

स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-21 के लिए निजी-सरकारी स्कूलों के खोलने और संचालन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार कक्षा 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय के लिए संचालित रहेंगे। बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। विद्यार्थियों को इस तरह बुलाया जाएगा कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक साथ अधिक ना हो, ताकि नियमों का पालन किया जा सके। समय-समय पर जारी विभागीय आदेश के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी, जो विद्यार्थी इस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ पूरी तरह उपस्थित रहेंगे।

छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के छात्रावासों को खोले जाने की अनुमति नहीं

आठवीं तक की कक्षाएं फिलहाल बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद इसको लेकर फैसला हो सकता है। वहीं कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए विद्यार्थियों की संख्या एवं उपलब्ध आयोजन कक्ष के आधार पर प्रायार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के छात्रावासों को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी। आवासीय विद्यालय डे-स्कूल रूप में खोले जा सकेंगे।

निजी स्कूलों के बदले सुर...अब धरना-प्रदर्शन स्थगित

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी होने के बाद निजी स्कूलों ने नरम रुख अपना लिया है। निजी स्कूलों द्वारा 16 दिसंबर को घोषित शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय प्रदेश के सभी अशासकीय शिक्षण संस्थानों के संचालकों की कार्यकारिणी बैठक के बाद लिया गया है। अब स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार ने प्रत्येक स्तर पर उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाया है, इसलिए उनके द्वारा घोषित शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम अभी स्थगित कर दिया गया है।

नियमों की अवहेलना करने वालों की मान्यता होगी रद्द

नए स्कूल शिक्षा विभाग ने अभिभावकों और बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अभिभावक इससे संतुष्ट हैं। नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर तत्काल कारवाई की जाएगी और मान्यता रद्द किए जाएंगे।

कमल विश्वकर्मा, अध्यक्ष

कमजोर विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय विद्यालयों में एक घंटे होगी पढ़ाई

कोरोना महामारी के कारण छात्रों के लिए कक्षाएं इस साल बाधित हुई हैं। ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन विद्यालयों को खोलने पर विचार कर रहा है। कयास लगाए जा रहे थे कि 15 दिसंबर से कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जाएगा, लेकिन राजधानी में केंद्रीय विद्यालयों में मंगलवार को कक्षाएं शुरू नहीं हो सकी। जानकारों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय बुधवार से ऐसे विद्यार्थियों के लिए आंशिक रूप से कक्षाएं खोलने की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं। इन विद्यार्थियों को छोटे समूहों में बुलाया जाएगा और तैयारी कराई जाएगी। ताकि आगामी बोर्ड परीक्षाओं में वह विद्यार्थी बेहतर रिजल्ट ला सकें। यह बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूलों को इस संबंध में क्षेत्रीय स्तर पर भी एक योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्कूलों को इससे पहले 21 सितंबर में भी खोलने की योजना बनाई थी। लेकिन अभिभावकों की सहमति न मिल पाने से इसे टाल दिया था। देश भर में करीब 1,250 केंद्रीय विद्यालय और 650 नवोदय विद्यालय हैं, जिनमें करीब 15 लाख छात्र पढ़ते हैं।

बीयूः परीक्षा में पास कराने वाला गिरोह सक्रिय, जांच के लिए कमेटी गठित

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) की गोपनीय शाखा में परीक्षा पास कराने वाला गिरोह सक्रिय है। इसकी शिकायत कोलार रोड निवासी लोकेंद्र द्वारा की गई थी।

इस संबंध में बीयू की कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार कुलपति प्रो. आरजे राव ने इसकी जांच के लिए एक सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस मामले की जांच रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. आशा मिश्रा करेंगी। लोकेंद्र द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि बीयू में छात्र-छात्राओं से पैसे लेकर पास कराने का गिरोह सक्रिय है। इसमें गोपनीय शाखा के अधिकारी, कर्मचारी भी

मिले हुए हैं। आरोप है कि इन्ही अधिकारियों व कर्मचारियों की लड़कियों को गोपनीय शाखा में डी-कोडर्स का कार्य सौंपा गया है। इनके माध्यम से छात्र-छात्राओं के मूल्यांकन की गणना, पीएचडी की थीसेस कहां भेजी जाती है, किसके पास भेजी गई है। यह बात पता चल जाती है, उसके बाद सेटिंग कर ली जाती है।

मंत्री सारंग ने संभागायुक्त को दिए निर्देश

असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में चयनित बाहरी उम्मीदवारों की ज्वॉइनिंग पर लगाई रोक

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

गांधी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंड प्रोफेसर की भर्ती में बाहरी उम्मीदवार को मौका देकर कार्यरत उम्मीदवारों को दरकिनार करने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने संभागायुक्त और जीएसमी को डीन का तलब कर तत्काल बाहरी उम्मीदवारों की ज्वानिंग पर रोक लगा दी है। मंगलवार को मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के 150 से ज्यादा डॉक्टर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात कर भर्ती में हुए भेदभाव के बारे में बताया। एसोसिएशन की बात को गंभीरता से लेते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि कार्यरत डॉक्टरों के भेदभाव नहीं होगा। जिन पदों पर बाहरी उम्मीदवारों की भर्ती की गई है उसे रिजेक्ट कर कार्यरत डॉक्टर को मौका दिया जाएगा। मंत्री सारंग ने संभागायुक्त को बाहरी उम्मीदवारों की भर्ती पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

- **चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने संभागायुक्त और डीन को किया तलब... कार्यरत डॉक्टरों की बजाए बाहरी उम्मीदवारों का क्यों किया चयन?**

डॉक्टरों की नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर की

एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. संजीव गौर और सचिव डॉ. राकेश मालवीय ने मंत्री को बताया कि पहले से काम कर रहे डॉक्टरों की अनदेखी कर बाहरी डॉक्टरों की नियुक्ति दे दी गई। डीन डॉ. अरुणा कुमार ने मनमानी करते हुए बाहरी डॉक्टरों की नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर की है। इसके विरोध में मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मिले और अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया। मंत्री ने एसोसिएशन की मांग को मानते हुए बाहरी उम्मीदवारों की भर्ती पर रोक लगा दी है।

पीईबी ने जारी किए डाहेट के रिजल्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने डिप्लोमा इन हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट-2020 (डाहेट) का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था रिजल्ट देखने के लिए एमपी पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। डाहेट-2020 का आयोजन 5 से 7 नवंबर 2020 तक आयोजित किया गया था। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा प्रदेश के पांच वेटनरी पॉलीटेक्नीक कॉलेजों में द्विवर्षीय पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 315 सीटों पर प्रवेश के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था।

व्याख्याताओं की वेतन विसंगति दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग में प्रक्रिया शुरू

एक दिन पहले व्याख्याता मिले थे पीएस से, मंगलवार को दिन भर हुई भागदौड़

भोपाल (आरएनएन)। प्रदेश में उम्रदराज होकर लगातार रिटायर हो रहे व्याख्याताओं की ताकत का एहसास शिक्षा विभाग को हुआ है। एक दिन पहले ही लेक्चरारों और प्राचार्य का एक दल विभाग की प्रमुख सचिव से मिला था, जहां वेतन विसंगति से होने वाले अनेक नुकसान गिनाए गए थे। अगले ही दिन मंगलवार से इस विषय में काम शुरू हो गया है। मंगलवार को मंत्रालय और लोक शिक्षण संचालनालय के बीच लगातार जानकारी जुटाने का काम चला। दूरभाष पर संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों से भी संपर्क हुए।

बताना होगा कि व्याख्याताओं ने अपनी वेतन विसंगतियों को लेकर सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी से मुलाकात की थी। व्याख्याता एवं प्राचार्य संवर्ग की समस्यायों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश शिक्षक संघ, प्रांतीय शासकीय शालेय व्याख्याता एवं प्राचार्य संघ, समग्र शिक्षक व्याख्याता एवं प्राचार्य कल्याण संघ, एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रमुख पदाधिकारियों क्रमशः छत्रवीर सिंह राठौर, महामंत्री शिक्षक संघ, के के गौर संभागीय अध्यक्ष शिक्षक संघ, प्रदेश अध्यक्ष अरुण विश्वकर्मा, मुकेश शर्मा एवं प्रांतीय संयोजक पीएस परिहार सहित प्रमुख प्रांतीय पदाधिकारी भरत व्यास, सुधाकर पाराशर, डॉ अनिल कुशवाहा, हरेंद्र सिंह, रविकान्त जैन, सीएस सोलंकी, बहन श्रीमती भावना शर्मा एवं श्रीमती संगीता सक्सेना सहित अन्य साथी उपस्थित रहें।

शिक्षकों को पदोन्नति पदनाम के विषय में भी सोचना होगा

इधर शिक्षक और सहायक शिक्षकों ने भी पदोन्नति पदनाम के लिए विभाग पर दबाव बनाया है। सहायक शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संयोजक सुभाष शर्मा का कहना है कि विभाग को इस विषय में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री की घोषणा को हुए पूरे 5 साल बीत चुके हैं लेकिन आज तक इसका पालन नहीं किया गया है। शर्मा का कहना है कि जबसे घोषणा हुई तब से अभी तक प्रदेश में दर्जनों शिक्षक बिना पदोन्नति पदनाम का लाभ लिए रिटायर हो गए हैं। विभाग का यह रवैया शिक्षकों के प्रति न्याय संगत नहीं कहा जाएगा।

प्रमुख सचिव शमी ने प्रमुख मुद्दों पर जताई थी सहमति

बैठक में व्याख्याता, प्राचार्य संवर्ग की समस्याओं एवं वेतन विसंगति से संबंधित सभी बिंदुओं पर प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, उप सचिव अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत संचालक लोक शिक्षण केके द्विवेदी, सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा कर की गई। दल का नेतृत्व भरत व्यास द्वारा किया गया एवं विसंगति के बारे में प्रमुख सचिव एवं सभी अधिकारियों को विस्तार से बताया। प्रमुख सचिव द्वारा ध्यान से पूरी बात सुनी एवं निर्देश दिए कि व्याख्याताओं की विसंगति संबंधी फाइल को तैयार कर मेरे अवकाश से लौटने पर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। हाईस्कूल प्राचार्य का पद समाप्त करने के संबंध में भी चर्चा की गई जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

18 से हायर सेकेण्ड्री और हाईस्कूल की लगेंगी कक्षाएं

हायर सेकेण्डरी और हाईस्कूल का रिजल्ट बिगड़ने का भी डर है। जिसको लेकर स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है मगर सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आयोजित होंगी।

कोविड की गाइड लाइन का सख्ती से करना होगा पालन

स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्कूलों में सेनेटाइजेशन की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार निर्धारित क्रम में बैठाना होगा। छात्रों को अपना पानी खुद लाना होगा और स्कूल में रहते वक्त हमेशा मास्क पहने रहना होगा। वहीं स्कूल के स्टाफ को भी इन्हीं प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके अलावा स्कूल संचालक की यह जिम्मेदारी बनेगी कि वह नियमित रूप से कक्षाओं को सेनेटाइज करे। बार-बार छूने वाली सतह जैसे दरवाजे का हैंडिल, बेंच, कुर्सी, वाशरूम आदि को नियमित रूप से साफ करना होगा।

प्रेक्टिकल परीक्षाएं भी होंगी

ज्ञात हो कि दसवीं और बारहवीं कक्षा में 20 से 25 प्रतिशत अंक प्रेक्टिकल के होते हैं। अब तक स्कूल संचालकों को यह असमंजस था कि वह बिना छात्रों को बुलाए प्रेक्टिकल कैसे आयोजित करा पाएंगे मगर वह समस्या अब समाप्त हो गई है। स्कूल शुरू होने के कुछ दिन बाद प्रेक्टिकल कराने की भी डेट जारी हो जाएगी।

9वीं और 11वीं कक्षाओं के लिए चल रहा मंथन

भोपाल स्तर पर कक्षा 9वीं और 11वीं की क्लासेस भौतिक रूप से शुरू करने को लेकर मंथन चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के संचालन के एक हफ्ते बाद 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी शुरू हो सकती हैं। बताया गया है कि अगर स्कूलों में जगह रहती है तो प्राचार्य 9वीं और 11वीं की कक्षाएं स्वयं से बुला सकते हैं। गौरतलब है कि दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं फरवरी और मार्च के पहले आयोजित हो जाती हैं मगर इस बार दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं संभवतः मार्च के अंत तक संपन्न होंगी और बोर्ड की परीक्षाएं 15 अप्रैल के बाद आयोजित हो सकती हैं।

18 दिसम्बर से राज्य सरकार के निर्देशानुसार 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं प्रारंभ होंगी। सभी प्राचार्यों के पास टेम्प्रेचर मापने वाली मशीन है। इसके अलावा सेनेटाइजर व मास्क की व्यवस्था होगी। 9वीं और 11वीं की कक्षाएं जगह को देखते हुए प्राचार्य खुद संचालित करा सकेंगे।

– रामनरेश पटेल, डीईओ रीवा

पथरिया कॉलेज ने वार्षिक पत्रिका में छुपाई नव चयनितों की योग्यता

प्रूफ रीडिंग किए बिना छाप दी अतिथि विद्वानों की जानकारी

पीपुल्स संवाददाता • पथरिया

नगर का सरकारी कॉलेज अपने कारनामों से बाज ही नहीं आ रहा है और न ही सुधार की कुछ गुंजाइश वर्तमान में दिखाई दे रही है। इस कॉलेज की मनमानी के इतने चर्चे है कि लगता है अब यहां से कुछ गुणवत्ता हासिल नहीं हो सकती, यह विभाग सिर्फ मोटी तनख्वाह और कमाई के लिए जाना जाता है। शिक्षा और शोध तो कोसों दूर है।

कुछ दिनों पहले ही यहां एक छात्र ने आरोप लगाया था कि नवचयनित नहीं पढ़ाते तो प्रबंधन ने छात्र को ही नोटिस थमा दिया था। इसके पहले भी नवचयनित सहायक प्राध्यापकों के

विवाद, अपडाउन, परिवीक्षा अवधि में नोटिस, दस्तावेजों की जांच इत्यादि की खबरें चर्चा में रही।

वार्षिक पत्रिका में छुपा ली नवचयनित सहायक प्राध्यापकों की योग्यता: अब एक नया मामला

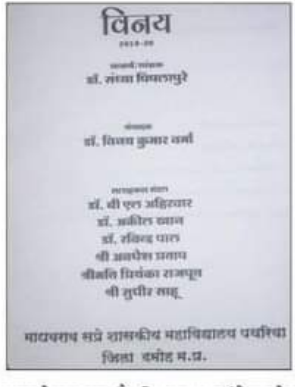

सामने आया है कि इस कॉलेज ने अपनी वार्षिक पत्रिका को सार्वजनिक कर दिया है। इसमें संदेह और ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इस पत्रिका में नवचयनित सहायक प्राध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता को छुपा लिया गया है और अतिथि विद्वानों की योग्यता को प्रकाशित कर दिया है, लेकिन उसमें भी दो अतिथि विद्वानों की गलत जानकारी छाप दी गई है। आश्चर्यजनक पहलू यह है कि कॉलेज की वार्षिक पत्रिका छात्रों को प्रदान तो की जाएगी। जानकारों के अनुसार कॉलेज प्रबंधन द्वारा जानबूझकर नव चयनितों की योग्यता को छुपाया गया है, क्योंकि इनमें से कुछ के पास संबंधित विषय को पढ़ाने की डिग्री/योग्यता ही नहीं होगी। बहरहाल, यह कॉलेज का कोई नया कारनामा नहीं है, क्योंकि जानकारी छुपाने और भ्रमित खबरें देने में इनका प्रबंधन वर्षों से माहिर रहा है। स्थानीय लोगों को आसानी से साध लेता है।

विवादों में रहता है प्रबंधन

पिछले वर्षों में यहां अनावश्यक उपकरणों की खरीदी भी की गई थी, जो आज तक इस्तेमाल नहीं हुई। यहां लगभग 28 वर्षों से पदस्थ डॉ. बाबू एल अहिरवार, सहायक प्राध्यापक की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठते रहे है जो 6 महीने बाद रिटायर होने वाले है।

नहीं दिया संतोषजनक जवाब

इस संबंध में जब पत्रिका के प्रभारी विनय वर्मा से पूछा गया कि नवचयनित की योग्यता नहीं लिखी तो इनका कहना था कि कहीं-कहीं चूक हो जाती है, इतना कह कर बात को इतिश्री कर दिया।

लॉ एग्जाम जनवरी के पहले सप्ताह में ऑनलाइन, साढ़े 9 हजार छात्र होंगे शामिल

भास्कर संवाददाता | इंदौर

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के लॉ कोर्स की परीक्षाएं जनवरी के पहले सप्ताह में ऑनलाइन होगी। इसमें साढ़े 9 हजार छात्र शामिल होंगे। मंगलवार को प्रबंधन की बैठक में ये परीक्षाएं ऑनलाइन कराने का फैसला लिया गया। प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। छात्रों को तीन घंटे में पेपर हल कर कॉपी अपलोड करना होगी। यह पहली बार होगा जब यूनिवर्सिटी किसी कोर्स की पूरी परीक्षाएं ऑनलाइन करवाएगी। यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर डॉ. अशेष तिवारी का कहना है जनवरी के पहले सप्ताह में परीक्षाएं होंगी। ऐसे में जल्द से जल्द इसकी तैयारियां की जाएंगी। दरअसल, बीसीआई (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) ने लॉ कोर्स के जनरल प्रमोशन के नतीजों पर रोक लगा दी थी। कोरोना संकट के कारण परीक्षाएं नहीं हो सकी थीं। ऑनलाइन परीक्षाओं में साढ़े नौ हजार छात्र शामिल होंगे। इनमें बीए-एलएलबी चौथे, छठवें और आठवें सेमेस्टर, एलएलबी पहला, दूसरा सेमेस्टर शामिल है। इसके अलावा बीकॉम, बीबीए एलएलबी चौथे, छठवें और आठवें सेमेस्टर की भी परीक्षाएं भी शामिल हैं।

निकाय चुनाव...इस माह के आखिरी हफ्ते में हो सकती है घोषणा

जिलों को सामग्री बांटने का काम 19 दिसंबर से शुरू हो जाएगा

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में अब और तेजी आने लगी है। चुनाव के लिए जिलों को सामग्री बांटने का काम 19 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। चुनाव के लिए प्रशिक्षण का काम भी लगभग पूरा हो गया है। 16 दिसंबर को दो नगर परिषद की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा और 17 दिसंबर को उसके प्रकाशन का प्रमाणपत्र पोर्टल में अपलोड होने के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। बाकी स्थानों पर वोटर लिस्ट का काम पूरा हो चुका है। चुनाव के लिए जिलों को जरूरी किताबों, प्रपत्र आदि का वितरण 22-23 दिसंबर तक कर दिया जाएगा। अमिट स्याही जल्द ही आयोग को मिलने वाली है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है।

चुनाव कार्य में जरूरी पीतल की सील भी बनकर तैयार हैं। जिलों में जरूरत के हिसाब से इन्हें दिया जाएगा। इस बीच तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की जिलों के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठकों का दौर चल रहा है। इसमें जिलों को निर्देश दिए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों से समन्वय भी किया जा रहा है। आयोग के सूत्रों के अनुसार निकाय चुनाव दो चरण में कराने का फैसला लगभग हो चुका है। इसके हिसाब से ही तैयारियां की जा रही हैं।

अब महिला अतिथि विद्वानों ने संभाला मोर्चा

मानदेय के लिए कुलपति, कुलसचिव का किया घेराव

स्टार समाचार | रीवा

मई महीने से मानदेय न पाने वाले अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अतिथि विद्वान पिछले दो हफ्ते से आंदोलनरत हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें मई और जून महीने का मानदेय देने का प्रस्ताव दे रहा है मगर अतिथि विद्वानों को नवम्बर महीने तक का मानदेय चाहिए। मंगलवार को महिला अतिथि विद्वानों ने मोर्चा संभाला और विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव का घेराव किया। मगर मंगलवार को भी अतिथि विद्वान और विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच में बातचीत नहीं बनी। अतिथि विद्वानों का आरोप है कि जब कार्य परिषद ने उन्हें मानदेय देने की स्वीकृति दे दी है तो विश्वविद्यालय का वित्त विभाग अड़ंगा क्यों बन रहा है। वहीं यह बात भी सामने आ रही है कि अतिथि विद्वानों को कार्य दिवस के अनुसार मानदेय देने का प्रावधान है और लॉक डाउन के बाद से लम्बे वक्त तक कक्षाओं का संचालन नहीं हुआ। ऐसे में किस आधार पर अतिथि विद्वानों का भुगतान किया जाए। वहीं अतिथि विद्वानों का कहना है कि उन्हें मई से लेकर नवम्बर माह तक का मानदेय चाहिए।

18 को बुलाई गई आपात बैठक

अतिथि विद्वानों के प्रदर्शन को देखते हुए कुलसचिव ने आपात बैठक बुलाई है। सिर्फ अतिथि विद्वानों के मसले को लेकर 18 दिसम्बर को ईसी सदस्य बैठेंगे और इस मुद्दे पर फैसला लेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों हुई आपात ईसी बैठक में कार्य परिषद ने अतिथि विद्वानों को मानदेय जारी करने का फैसला लिया था, जिस पर वित्त नियंत्रक ने टीप दी थी। अब फिर से एक बार इसी मुद्दे पर ईसी बैठक होगी। अब देखना है कि कार्य परिषद इस मामले में क्या फैसला लेता है और वित्त विभाग कार्य परिषद के निर्णय को स्वीकार करता है या नहीं।

कक्षाएं हो रहीं प्रभावित

गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स और सहायक प्रोफेसर्स से कई गुना ज्यादा अतिथि विद्वान हैं और अतिथि विद्वान ही अध्ययन अध्यापन का ज्यादातर कार्य संभालते हैं। पिछले दो हफ्ते से चल रहे आंदोलन के कारण विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले छात्रों को कोई पढ़ाने वाला नहीं रह गया है। ऐसे में उनके सेलेबस के अधूरे रह जाने का भी डर है। ऐसा बताया गया है कि जितनी अवधि तक अतिथि विद्वानों का आंदोलन चलता रहेगा और वह कार्य से बाहर रहेंगे, उस दौरान का मानदेय उन्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि अतिथि विद्वानों को कार्य दिवस के अनुसार ही मानदेय मिल जाता है।

ईसी मेंबर ने पीएचडी की परीक्षा शीघ्र कराने की मांग की

ग्वालियर (नप्र)। जीवाजी विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद सदस्य डा. संगीता चौहान ने कुलसचिव को ज्ञापन सौंपकर पीएचडी की परीक्षा शीघ्र कराए जाने की मांग की है। ईसी मेंबर ने बताया कि पिछले दो साल से पीएचडी की प्रवेश परीक्षा नहीं हुई है। इससे विद्यार्थी परेशान हैं। ऐसी क्या असमर्थता है कि परीक्षा नहीं कराई जा रही है। यह परीक्षा शीघ्र कराई जाए। विवि में एक परामर्श खिड़की खोली जाए। जेयू में देखने में आ रहा है कि विद्यार्थी जानकारी के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं। दो लोगों को परामर्श की खिड़की पर बिठाया जाए। इसके अलावा आंचलिक केंद्र खोला जाए। कुलसचिव ने शीघ्र समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है।

लापरवाही

जेयू सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में टॉप पर, इस सत्र में ज्यादा शिकायतें रिजल्ट की, विदहेल्ड को नहीं कर रहे क्लीयर

जेयू को परीक्षाएं करानी पड़ीं न कॉपियों की जांच, फिर भी शिकायतें बढ़ीं

ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जीवाजी विश्वविद्यालय में लगातार सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यह आंकड़ा ऐसे समय बढ़ रहा है, जब जेयू को परीक्षाएं आयोजित नहीं करानी पड़ीं, न कॉपियों की जांच। सिर्फ रिजल्ट घोषित करने पड़े हैं। सही रिजल्ट नहीं मिल जाने की वजह से विद्यार्थी परेशान हैं। इस कारण छात्र सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। क्योंकि उनकी शिकायतों का जेयू में कोई निराकरण नहीं हो रहा है। रिजल्ट विदहेल्ड से जुड़े मामले ज्यादा बढ़े हैं। सीएम हेल्पलाइन को लेकर मंगलवार को भी अधिकारी गंभीरता नहीं बरतते रहे। कुलसचिव आनंद मिश्रा का कहना है कि इस कारण पता नहीं है, शिकायतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं।

शिकायतों पर अफसरों से चर्चा करते कुलसचिव आनंद मिश्रा। ● नईदुनिया

जीवाजी विश्वविद्यालय सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में टॉप पर है। गत वित्त कलेक्टर ने भी जेयू की सीएम हेल्पलाइन से संबंधित शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए सहायक कुलसचिव को फटकार लगाई थी। इनके निराकरण के लिए दो दिन का समय दिया था। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग को जेयू के संबंध में कार्रवाई के लिए लिखने का चेतावनी भी दिया। कलेक्टर की फटकार का दूसरे दिन जेयू ने जवाब दिया। मंगलवार को कुलसचिव ने उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव की बैठक ली। शिकायतों के निराकरण के लिए दो दिन का समय दिया था। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग को जेयू के संबंध में कार्रवाई के लिए लिखने का चेतावनी भी दिया। कलेक्टर की फटकार का दूसरे दिन जेयू ने जवाब दिया। मंगलवार को कुलसचिव ने उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव की बैठक ली। शिकायतों एल-3 व एल-4 स्तर पर पहुंच गई हैं, जिनके निराकरण में अधिकारी लगे हुए हैं। इस वर्ष सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की संख्या अधिक है।

कोविड-19 की वजह से बदली व्यवस्था: कोविड-19 की वजह से जेयू को स्नातक तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन बुक प्रणाली से आयोजित करानी पड़ी। स्नातक की कॉपियों का मूल्यांकन लोड कालेजों ने कराया, जबकि स्नातकोत्तर की कॉपियों के मूल्यांकन की जिम्मेदारी जेयू की थी। स्नातकोत्तर में विद्यार्थियों की संख्या काफी कम थी। स्नातक तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा को छोड़ शेष परीक्षाओं में विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया गया। जनरल प्रमोशन के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं करानी पड़ी। जेयू को रिजल्ट घोषित करना पड़ा।

इस तरह की शिकायतों की संख्या अधिक

- जेयू के डाटा में गड़बड़ी है, इससे विद्यार्थियों के रिजल्ट विदहेल्ड हो गए हैं। जेयू में टोकन जमा करने के बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परेशान विद्यार्थी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा रहे हैं।
- कॉपियों में नंबर छोड़ दिए हैं। विद्यार्थी अपनी कॉपी निकालकर रिजल्ट में सुधार कराने आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
- मार्कशीट में भी गलतियां हैं। ये गलतियां आसानी से ठीक नहीं हो रही हैं। इस कारण विद्यार्थी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं।
- जेयू ने कुछ रिजल्ट भी घोषित नहीं किए हैं। इन रिजल्टों को लेकर भी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं।

सीएम हेल्पलाइन की स्थिति

एल-1-455	एल-3-46
एल-2-126	एल-4-3

हम मंथन कर रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं। छात्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए जिम्मेदारी दी है। पुरानी कॉपी से रिजल्ट का डाटा लिया है और रिजल्ट में सुधार किया जा रहा है।

आनंद मिश्रा, कुलसचिव जेयू

इग्नू ने बढ़ाई परीक्षा फार्म भरने की तारीख

भोपाल(नरि)। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने दिसंबर की टर्म परीक्षा के लिए परीक्षा फार्म भरने और असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इसके अनुसार अब छात्र 31 दिसंबर तक दिसंबर टर्म परीक्षा के लिए फार्म भर सकते हैं। साथ ही असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और डिजर्टेशन भी अब 31दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर थी। परीक्षा फरवरी में होगी।

सीए के विभिन्न कोर्स की परीक्षाएं 21 जनवरी से

भोपाल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) की नवंबर माह से शुरू हुई परीक्षाएं सोमवार को समाप्त हो गई। आइसीएआइ ने 2021 में होने वाली परीक्षाओं की तारीख भी घोषित कर दी है। परीक्षा 27 जनवरी से सात फरवरी तक होगी। नवंबर में जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाए थे वे भी इसमें शामिल हो सकेंगे। जनवरी से होने जा रही परीक्षाओं में इंटरमीडिएट ओल्ड और न्यू कोर्स की ग्रुप एक की परीक्षा 22, 24, 27 और 29 जनवरी को होगी। वहीं ग्रुप दो की परीक्षा एक, तीन और पांच फरवरी को आयोजित होगी। न्यू कोर्स के तहत सात फरवरी को इंटरमीडिएट कोर्स की अतिरिक्त परीक्षा ली जाएगी। सीए फाइनल परीक्षा में ओल्ड और न्यू सिलेबस की ग्रुप एक की परीक्षा 21, 23, 25 और 28 जनवरी को होगी। ग्रुप दो की 30 जनवरी और दो, चार और छह की फरवरी में होगी। कोरोना के कारण परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। (नरि)

यूनिवर्सिटी का फैसला एलएलबी-एलएलएम समेत अन्य लॉ कोर्स की जनवरी पहले सप्ताह में ऑनलाइन होगी परीक्षा

वेबसाइट पर जारी होंगे पेपर, विद्यार्थियों को अपलोड करनी होगी उत्तरपुस्तिका

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। विभिन्न लॉ कोर्स की परीक्षा को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। जनवरी पहले सप्ताह में वर्कशीट परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाया जाएगा। जहां विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पेपर जारी किए जाएंगे। तीन घंटे में जवाब लिखकर विद्यार्थियों को विशेष लिंक पर उत्तरपुस्तिका अपलोड करनी होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने घंटेभर का समय निर्धारित किया है। उच्च अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के बेहतर संचालन के लिए 30 दिसंबर को मॉक टेस्ट की व्यवस्था रखी है।

दस महीने से अटकी लॉ कोर्स की परीक्षाओं के संचालन को लेकर विश्वविद्यालय में कॉलेज प्राचार्य और डीन की बैठक बुलाई है। बीपीबार तीन बजे से शाम पांच बजे तक मंथन किया गया। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक तिवारी, डिप्टी रजिस्ट्रार प्रज्ञकल खरे, रचना ठाकुर समेत 13 कॉलेजों के प्राचार्य शामिल हुए। जहां एलएलबी के पहले-चौथे,

बीएएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी के दूसरे, चौथे, छठे और एलएलएम में तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं पर चर्चा हुई। जनवरी पहले सप्ताह में ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक कॉलेज को अपने-अपने विद्यार्थियों पर मुख्य सीट से नजर रखनी है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा से ठीक दस मिनट पहले पेपर अपलोड किया जाएगा। तीन घंटे में विद्यार्थियों को जवाब लिखना है। अधिकारियों के मुताबिक विशेष लिंक विद्यार्थियों को बताई जाएगी, जिसमें उत्तरपुस्तिका को स्कैन कर अपलोड करना होगा। ये सीधे विश्वविद्यालय के पास पहुंचेगी। परीक्षा में नौ हजार विद्यार्थी शामिल होंगे।

परीक्षा नियंत्रक डॉ. तिवारी का कहना है कि परीक्षा से पूर्व एक मॉक टेस्ट किया जाएगा। इसमें परीक्षा को बेहतर ढंग से करने की व्यवस्था पर जोर देंगे। ये टेस्ट 30 दिसंबर को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी कॉपी अपलोड नहीं कर सकते हैं। वे अपने कॉलेज में मूल कॉपी जमा करवा सकते हैं। इसके लिए भी सिर्फ एक घंटे का समय दिया जाएगा।

• • • • • • • • • • •

आज का इतिहास

- **1631** : इटली के माउंट विसुवियस म
ज्वालामुखी विस्फोट से छह गांव तबाह
चार हजार से अधिक लोग मारे गये।
- **1707** : जापान के माउंट फुजी पर्वत म
अंतिम बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ
- **1862** : नेपाल में संविधान लागू हुआ
- **1889** : ब्रिटिश संसद की अधिका
घोषणा को राजा विलियम और रानी
मेरी ने स्वीकृत कर शासन में जनता के
अधिकार को मान्यता दी।
- **1920** : चीन के कांसू प्रांत आए भूकंप
के कारण से एक लाख से अधिक लोग
की मौत।
- **1927** : आस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज
सर डॉन ब्रैडमैन ने न्यूसाउथ वेल्स और
दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच से
अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की
शुरुआत की।

आज का इतिहास

1937 हवा सिंह - भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक का जन्म हुआ।

1971 सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल - परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक का निधन हुआ।

1993 नई दिल्ली में सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन प्रारम्भ।

1994 पलाऊ संयुक्त राष्ट्र का 185वां सदस्य बना।

2006 नेपाल में अंतरिक्ष संविधान को अंतिम रूप दिया गया। इसके तहत राजा ज्ञानेन्द्र को देश के प्रमुख के पद से हटा दिया गया।

2008 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण को गठित चड्ढा समिति की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार ने मंजूर किया।